

→ राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील

राष्ट्रपति रूजवेल्ट का 'नया व्यवहार' (NEW DEAL) आर्थिक मंदी से निवटने एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु किया गया एक प्रयत्न था। रूजवेल्ट कोई 'अर्थनीति विचारद' न थे बल्कि सामान्य समझ रखने वाले एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उनके विचारों में एक ओर जहाँ लचीलापन था तो दूसरी ओर समझाओं से लड़ने-झिड़ने का दृष्टिकोण भी। उन्हें पूँजीवादी या समाजवादी सिद्धांतों की शास्त्रीय चिंता नहीं। वे समझाओं के वस्तुनिष्ठ समाधान चाहते थे। यही कारण है कि एक ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका घोर आर्थिक अराजकता में डूबा था, अर्थशास्त्री एवं राजनेता किंकर्तव्यविमूढ़ थे तथा पुरातन परम्परावादी अदृष्टक्षेप के सिद्धांत (लैसजकेयर) को पकड़ बैठे थे रूजवेल्ट ने अपनी 'सामान्य चेतना' से राज्य के कर्तव्य की परिभाषा का पुनर्निर्धारण किया तथा अर्थव्यवस्था में दृष्टक्षेप का निर्णय लिया जो 'न्यू डील' कहलाया।

कागज़ से देखें तो 'न्यू डील' में कोई नवीनता नहीं। अमेरिका के लिए यह नवीन हो सकता था, परंतु यूरोप में यह सर्वस्वीकृत था। इसके अन्तर्गत रूजवेल्ट ने पूँजीवादी विचारधारा के पोषक 'अदृष्टक्षेप के सिद्धांत' को छोड़ दिया तथा अर्थव्यवस्था में दृष्टक्षेप का निर्णय किया। 1932 में रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति चुने जाने पर अपनी जनता को भरोसा दिलाते हुये एक 'नया व्यवहार' देने की घोषणा की। इसके ठीक तीन दिनों बाद शुरू अमेरिकी कांग्रेस के सत्र दिन के अधिवेशन में कई विधेयक पास किये गये जिसकी मूल प्रेरणा थी - आर्थिक मंदी से निवटने एवं एक अधिक विकास समृद्धि की स्थापना।

उत्पादन की अल्पता ने नदी, कृषकर्मियों के बुनियादी अख्यान वितरण से मंदी को आमंत्रित किया था इसीलिए आम अमेरिकी जनता को कृषकर्मियों को मंदी-पूर्व की स्थिति में लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा गया। साथ ही कृषि एवं उद्योग एवं मजदूरी करनेवालों, रोजगार देनेवालों तथा उपभोक्ताओं के बीच संतुलन लाने की कोशिश की गयी।

क्षेत्रों में पूँजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी सम्पत्ति के असमान वितरण की समस्या को दूर कर उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की गयी।

आर्थिक संदी का प्रारम्भ 'कृषि क्षेत्र' ले हुआ था। कृषकों ने ऋण लेकर, फार्मों को गिरवी रख अत्यधिक उत्पादन की नीति अपनाई थी जिससे संदी का संकट और गहराया था। रूजवेल्ट ने 'कृषि समायोजन कार्यक्रम' पारित कर कृषकों से उत्पादन क्षेत्र में कटौती का आह्वान किया। जितना क्षेत्र कृषक रिक्त छोड़ता उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की। कृषकों ने इसे सहर्ष स्वीकार तो नहीं किया, परंतु रूजवेल्ट की इस नीति के लक्ष्यकार्यक परिणाम हुए।

रूजवेल्ट ने उत्पादकों, श्रमिकों एवं कृषकों को पारस्परिक सहयोग के लिए आह्वान किया। 'राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम' (NIRA) को 1933 में पारित किया इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापार एवं उत्पादन का नियंत्रण, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटों में कमी तथा मूल्य वृद्धि आदि थे। इस अधिनियम से आशा की गई कि जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि होगी और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। NIRA की व्यवस्थाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 'राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्रशासन' की स्थापना की गयी। इसमें विशेषज्ञों का एक दल था और उद्योग तथा श्रम के प्रतिनिधि रखे गये थे। ये लोग मिलकर उचित संहिताएँ बनाते, सिकायत सुनते थे और संहिताओं का कार्यरूप में परिणत कराते थे। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रोजगार एवं मजदूरी में 1933 के अंत तक 37 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 96 प्रतिशत निभोजनों ने अपनी सहमति दी। हालांकि 1935 में NIRA को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धाराओं के प्रतिष्कूल बताकर अवैध घोषित कर दिया। तत्पश्चात् 1935 में वेग्नर ऐक्ट (Wagner Act) पारित कर श्रम संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। 1938 में Fair Labour Standard Act पारित कर. दृष्टान्त अधिकतम यालीय घंटे काम करने तथा प्रति घंटा व्यापारिक पारिश्रमिक निर्धारित करने की व्यवस्था की गई साथ ही बच्चों को काम

करने पर रोक लगा दी गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने ठपूडील के तहत सामाजिक-आर्थिक प्रत्युत्थान नीति पर जोर दिया। इसकी सक्ते क्रान्तिकारी योजना सामाजिक-सुरक्षा अधिनियम था जिसे 1935 में लागू किया गया। इसके तहत संघीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की जो प्रकृति और बाल-कल्याण, अंधे-अपंगों एवं अपाहिजों की पुनःस्थापना के संबंधित था। वृद्धों को सामाजिक-सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा योजना शुरू की गई जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक उम्रवाले लोगों के पोषण का भार राज्य सरकार ने ग्रहण किया। बेरोजगारी दूर करने हेतु 1933 में Unemployment Relief Act पारित किया गया तथा निरोजन कार्यालय खोले गये। Civil Conservation Corporation के जरिये अधिकांश बेकार लोगों को तमाम देश में फैली हुई लाखों योजनाओं में लगाया गया। 1940 तक 20 लाख युवकों को वनों, खेतों तथा बागानों में काम दिये गये। जनता को आवास सहायता हेतु 'संघीय आवास प्रशासन' की स्थापना की जिसका वृद्धतर रूप 1937 में 'संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण' की स्थापना करना था। अमेरिका के कई राज्यों को प्रभावित करने वाली 'टेनेसी घाटी परियोजना' के तहत कई बांध बनाये गये, विद्युत् उत्पादन शुरू हुआ, जंगल लगाये गये। इसके लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

मौद्रिक नीति में परिवर्तन लाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न की गई, बाजार में अतिरिक्त मुद्रा जारी की गई तथा औद्योगिक संस्थानों को व्यापक पैमाने पर ऋण देने की व्यवस्था की गई। बैंकों को ऋण दिया गया ताकि उनकी सार्व वनी रहे। स्वर्णिमान का परिभाषा किया गया तथा आयात को घटाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए डॉलर के अवमूल्यन की नीति अपनाई।

रूजवेल्ट की इन नीतियों को समाजवाद से प्रभावित माना गया तथा प्रतिक्रियावादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्वयं व्यापकता ने इनमें से कई का असंवैधानिक करार दिया। वास्तव में अमेरिकी संविधान द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को विदेशों से तथा विभिन्न राज्यों के बीच वाणिज्य का विनियमन

करने की शक्ति मात्र प्रदत्त है। रूजवेल्ट की सरकार द्वारा इसी अधिनियम की घोड़ी खींचतान कर श्रम की अवस्थाओं का निवारण एवं मूल्य नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अपनाये जा रहे थे। यही कारण था कि उद्योग एवं कृषि को नियंत्रित करने तथा श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के कदमों को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्वैधानिक करार दिया पर जनता ने रूजवेल्ट को स्वीकार किया। वे इसके बाद तीन बार ^{लोकतंत्र} राष्ट्रपति पद पर चुने गये।

रूजवेल्ट का 'न्यू डील' समग्र रूप से सफल नहीं थी। उनकी इस नीति से आर्थिक दाय की प्रक्रिया मात्र अवरुद्ध हो गयी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी पूर्व की स्थिति को न पा सकी। मंदी के बादल द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत पर ही छंट सके। भुइजनिंग आवश्यकताओं ने अर्थव्यवस्था में त्वरण ला दिया।

रूजवेल्ट के कई सहायकों को समाजवाद से जोड़कर देखा जाता है एवं इस आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। वास्तव में उनका 'न्यू डील' पूंजीवादी तंत्र की विकलता को रोकने का एक प्रयत्न मात्र था। उन्होंने इसीलिए अदरलक्ष्य की नीति का परिचायक किया एवं अर्थव्यवस्था में समन्वय कायम करने की कोशिश की। 'न्यू डील' ने एक तरफ यह स्पष्ट कर दिया कि पूंजीवादी सिद्धांतों की रक्षा मात्र के लिए समाज एवं मानव कल्याण की बलि नहीं दी जा सकती, दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राज्य की आवश्यकता स्वीकारी। स्पष्टतः रूजवेल्ट की 'न्यू डील' में राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एक नयी और अधिक आशापूर्ण दिशा में प्रेरित करने की विचारशक्ति थी।

